ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

14/12/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

THE HINDU National

सीओपी 28 जीवाश्म ईंधन से 'दूर जाने' का आह्वान करता है

दुबई में सीओपी 28 बुधवार को दुबई सर्वसम्मति नामक एक प्रस्ताव को अपनाने के साथ समाप्त हो गया

दुबई आम सहमति के महत्वपूर्ण बिंदु:

- 21 पेज के दस्तावेज़ में स्टैंडआउट क्लॉज कहता है : "पार्टियों से आह्वान करता है (होने के लिए) ... ऊर्जा प्रणाली में जीवाश्म ईंधन से दूर, उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से, इस महत्वपूर्ण दशक में कार्रवाई में तेजी लाते हुए, शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए"2050 विज्ञान के अनुसार"।
- "ट्रांज़िशनिंग" भाषा को पहले के मसौदे से कमजोर कर दिया गया है जिसमें सभी जीवाश्म ईंधन को "चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने" का आह्वान किया गया था।

उत्सर्जन के पीछे जीवाश्म ईंधन का उपयोग मुख्य दोषी है और इस संबंध में कार्रवाई महत्वपूर्ण थी।

देशों के बीच अंतर:

- एक पर समोआ और मार्शल द्वीप समूह के प्रतिनिधि ने इस बात पर नाखुशी व्यक्त की कि दस्तावेज़ जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की बात नहीं करता है। दूसरी ओर सऊदी अरब, मिस्र, कोलंबिया और सेनेगल जैसे देशों ने कहा कि यह समझौता जीवाश्म ईंधन मुक्त भविष्य की दिशा में एक कदम है।

- एक बड़ी आलोचना विकसित देशों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए विकासशील देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कमी थी।2009 की एक प्रतिबद्धता में कहा गया था कि देशों को जलवायु वित्तपोषण के लिए 2020 और 2025 के बीच प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाना होगा। लेकिन प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई

- पेरिस समझौते के दौरान तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया था।

1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देशों को अपने उत्सर्जन को 2030 तक 2019 के स्तर से 43% तक कम करने की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान आकलन कहता है कि अधिकांश आशावादी परिस्थितियों में भी, देश 2030 तक सबसे आशावादी परिस्थिति से 5% कम करने में सक्षम होंगे।

लोकसभा में 2 आगंतुकों के धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई

संसद पर हमले की पूर्व संध्या पर बुधवार को दो व्यक्ति पीले धुएं वाले कनस्तर लेकर दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद पड़े। इससे अराजकता फैल गई, सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों को संभालने से पहले उन्हें पीटा।

लोकसभा अध्यक्ष ने बाद में बताया कि यह धुआं सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए था. दिल्लीम्पिलिकेन ने घटना में शामिल सभी छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में कोई आतंकी एंगल नहीं था। , घुसपैठिए और उनकी टीम केवल एक राजनीतिक विरोध का आह्वान कर रही थी जिसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। वे नौकरियां न होने और महंगाई से परेशान थे।

भारत ने इजराइल द्वारा गाजा में तत्काल युद्धविराम के पक्ष में मतदान किया

भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जिसमें तत्काल युद्धविराम, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा और सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया गया था। 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 10 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि 23 देशों ने इससे परहेज किया.

भारत के वोट के बारे में पूछे जाने पर इजराइल दूतावास ने कहा कि वह आतंकवाद पर पीएम मोदी के रुख की सराहना करता है।

भारत ने पहले इसी तरह के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया था। यह भारत के रुख में बदलाव को दर्शाता है।

फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर अंकुश लगाएं

नीति आयोग के प्रमुख विनोद के पॉल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने केंद्र सरकार को फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दी जाने वाली पेशकश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है।

पैनल द्वारा सुझाए गए उपाय हैं:

- ₹1000 से अधिक नहीं मूल्य वाले ब्रांडेड उपहारों का खुलासा करना।
- विदेशी स्थानों पर डॉक्टरों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यशाला पर रोक लगाना,
- फार्मा कंपनियों से मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा प्राप्त धन को कर योग्य बनाना।

वगैरह

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लद्दाख पर हमारी स्थिति नहीं बदलेगी

"चीन ने भारत द्वारा एकतरफा और अवैध रूप से स्थापित तथाकथित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत के घरेलू न्यायिक फैसले से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि चीन की भारत सीमा का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है," चीनी विदेश मंत्री माओ निंग ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही.

चीन लद्दाख पर अपना दावा करता है।

वैश्विक गिरावट के बावजूद भारत में सड़क मृत्यु दर में वृद्धि

सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2023 आ गई है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तैयार की गई है।

कुछ। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु ये हैं:

2010 और 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में 5% की कमी आई और यह सालाना 1.19 मिलियन हो गई। 108 देशों में गिरावट देखी गई।

भारत में यातायात दुर्घटनाओं की कुल संख्या 2010 में 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 लाख हो गई।

दस देश सड़क दुर्घटनाओं के कवरेज को 50% तक कम करने में सफल रहे। ये देश हैं बेलारूस, ब्रुनेई, दारिसल्मे, डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रूस फेडरेशन, त्रिनिदाद और टोबैगो और यूएई, वेनेजुएला।

35 देशों ने 30 से 50% के बीच गिरावट दिखाते हुए उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है।

2010 से 2021 की अवधि के दौरान वाहन वृद्धि 160% है।

10 में से नौ मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया

बुधवार को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) में 28 देशों और यूरोपीय संघ ने "नई दिल्ली घोषणा" को अपनाया।

घोषणापत्र "भरोसेमंद एआई के लिए जिम्मेदार नेतृत्व के सिद्धांतों...लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों में निहित..." के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। और भरोसेमंद, जिम्मेदार, टिकाऊ और मानव केंद्रित एआई को बढ़ावा देना”

"नई दिल्ली घोषणा" पर कुछ अन्य बिंदु हैं

ग्लोबल साउथ के लिए एआई: राजीव चद्रशेखरन ने कहा, "हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि जीएलएआई, ग्लोबल साउथ के देशों सहित साझेदार देशों के मूल्यों को बनाए रखेगा।"

एआई चिंताओं पर: "गलत सूचना और दुष्प्रचार, बेरोजगारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी, बौद्धिक संपदा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे के संबंध में चिंताएं"

पिछला शिखर सम्मेलन जापान में हुआ था, उस समय चैटजीपीटी नहीं आया था। यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि चैटजीपीटी के आने के बाद आयोजित किया जा रहा है जिसने एआई से उभरती नई प्रकार की चुनौतियों को दिखाया है।

World

गाजा में भीषण युद्ध के दौरान घात लगाकर किए गए हमले में नौ इजरायली सैनिक मारे गए

हमास के लड़ाकों ने गाजा शहर के पड़ोस शिजैया में 9 इजरायली सैनिकों को मार डाला।

गाजा सिटी और उसके आसपास भारी लड़ाई चल रही है. फ़िलिस्तीन में अब तक 18,400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

सुनक ने नेतृत्व की चुनौतियों से परहेज किया क्योंकि निर्वासन विधेयक शुरुआती वोटों से पारित हो गया

ब्रिटिश संसद ने अवैध प्रवासियों को रावंडा निर्वासित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। ब्रिटिश संसद ने इसे 313 से 269 वोटों से पारित कर दिया। इसे पीएम ऋषि सुनक की जीत के तौर पर देखा जा रहा है.

ऋषि सनक ने इस वर्ष "नावों को रोकने" का संकल्प लिया था, जिसके तहत 2022 में लगभग 46,000 लोग "छोटी नावों" में इंग्लिश चैनल पार करेंगे।

इससे पहले ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बिलरिटिश सरकार की रवांडा नीति को गैरकानूनी बताया है।

अदालत ने कहा था, रवांडा फिलहाल एक सुरक्षित देश नहीं है, जहां सरकार शरण चाहने वालों को स्थानांतरित कर सके। इसमें यह भी कहा गया था कि यह यूके को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीति के गलत पक्ष में डाल देगा।

नया बिल रवांडा को एक सुरक्षित देश के रूप में परिभाषित करता है

IMF ने श्रीलंका के लिए 337 मिलियन डॉलर की दूसरी किश्त को मंजूरी दी

आईएमएफ ने श्रीलंका को 337 मिलियन डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) को मंजूरी दे दी है।

यह श्रीलंका द्वारा आईएमएफ से मांगे गए 3 अरब डॉलर का हिस्सा है। इस किश्त सहित श्रीलंका को मिला कुल ऋण 670 मिलियन डॉलर है।

आईएमएफ ने कहा कि श्रीलंका ने ऋण स्थिरता बहाल करने, राजस्व बढ़ाने, रिजर्व बफर का पुनर्निर्माण करने, मुद्रास्फीति को कम करने और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने की दिशा में "सराहनीय प्रगति" की है। आईएमएफ ने कहा, "प्रशासन में सुधार और गरीबों और कमजोरों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है।"

चीन और वियतनाम को एशिया प्रशांत को मापने के प्रयासों का विरोध करना चाहिए: शी जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हनोई के दौरे पर हैं. दोनों देशों ने गहरे संबंधों के लिए प्रति बद्ध ताज ताई और 30 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों देशों के बीच रेल संपर्क विकसित करने की प्रतिज्ञाभीशामिल है।

इस दौरे को क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए देखा जा रहा है।

बिडेन ने यूक्रेन का समर्थन किया, पुतिन को जीतने की अनुमति न देने की चेतावनी दी

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लोदमीर ज़ेलेंस्की से कहा था कि अमेरिका रूस के खिलाफ अपनी हताश लड़ाई में यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा।

उन्होंने बताया कि यूक्रेन की हार की अनुमति देने का मतलब पुतिन और "हर जगह आक्रामकों को प्रोत्साहित किया जाएगा"।

वह वाशिंगटन में ज़ेलेंस्की के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बता रहे थे।

हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन ने 110 बिलियन डॉलर के फंड को पारित करने की अनुमति नहीं दी, जिसका उपयोग यूक्रेन और इज़राइल द्वारा किया जाना था।